जो मातृभाषा की अवगणना करता है, वह अपनी माता की करता है।
-महात्मा गांधी-

दैनिक
लोकजीवन
www.lokjeewan.com
जयपुर एवं भीलवाड़ा से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी त्रिवेदी

लोक जीवन में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें:-
- : जयपुर : -
0141-4038281
- : भीलवाड़ा : -
8306792625

वर्ष- 19 | अंक- 194 | जयपुर. शुक्रवार . | 13 नवम्बर , 2026 | RNI No. RAJHIN/2008/26744 | मूल्य 1 रूपया | पृष्ठ - 4

न्यूज इनबॉक्स

जयपुर में थार से कुचलकर युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जयपुर (कासं)। जयपुर में गुरुवार को एक बार फिर तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। थार ने पैदल जा रहे युवक को उसके घर के पास ही टक्कर मारी। इसके बाद ड्राइवर ने वापस गाड़ी को बैक किया और युवक को कुचला। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। युवक 18 भाई-बहन की मौत के बाद पैदा हुआ था और घर में इकलौता बेटा था। हादसा शास्त्रीनगर इलाके के नाहरी का नाका स्थित स्वामी बस्ती में दोपहर करीब एक बजे का है। युवक के परिजन और स्थानीय लोग आरोपी ड्राइवर को पकड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान युवक की बहन ललिता बोलीं- 'मेरे भाई के हत्यारे की लाश मेरी गोद में दे दो, जैसे मैं अपने भाई की लाश को गोद में लेकर बैठी हूं।' परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर कुचला गया है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सेकेंड बजरंग सिंह ने बताया कि हादसे में स्वामी बस्ती निवासी गणेश स्वामी (40) की मौत हो गई। थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। बंधा बस्ती निवासी शाहरुख, अरशद को डिटेन भी किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ललिता ने बताया कि उसका और भाई का घर पड़ोस में ही है। भाई मेरे घर पर पानी पीने के बाद वापस जा रहा था। इस दौरान थार ने टक्कर मार दी। मैं और मेरा चचेरा भाई दौड़कर गए। चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट थी। चाचा वेदप्रकाश सोलंकी ने कहा कि सुबह ही गणेश को अच्छे-भले देखा था। गणेश से पहले बड़े भाई के 18 बच्चे हुए थे, लेकिन कोई जीवित नहीं रह पाया था। गणेश के जन्म पर परिवार ने खुशियां मनाई थीं। गणेश मजदूरी करता था। परिवार में पत्नी आशा (39), बेटा सन्नी (15) और बेटी मोनिका (12) हैं।

विदेशियों के लिए भारत का वीजा सिस्टम हुआ आसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्रालय ने भारत के वीजा सिस्टम में बदलाव किया है। अब वीजा की मुख्य कैटेगरी 13 से घटाकर 9 और सब-कैटेगरी 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं। यानी विदेशियों के लिए वीजा चुनना और आवेदन करना आसान होगा। टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इसके अलावा वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम भी 65-70% कम कर दिए गए हैं। इससे पहले अक्टूबर 2025 में वीजा की मुख्य कैटेगरी 22 से घटाकर 13 और सब-कैटेगरी 63 से घटाकर 49 की गई थीं। नई व्यवस्था दिसंबर 2026 तक लागू हो जाएगी। फिलहाल भारत 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा देता है।

आप ने दूसरी सूची में 31 उम्मीदवारों को उतारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। नई दिल्ली में शाम को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद 31 नामों का एलान किया गया। पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। बैठक में सीएम भगवंत मान भी शामिल शामिल थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सर्वे में जो उम्मीदवार को आगे रह हैं उन्हें टिकट दी गई है। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार सर्वे में खरे नहीं उतरे इसलिए उनका टिकट काटा गया है। बता दें कि खरड़ से अनमोल गगन मान का टिकट काटा गया है। साथ ही लंबी से मंत्री गुरमीत सिंह की टिकट काट दिया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 31 अक्तूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। उसमें सीएम भगवंत मान समेत 40 उम्मीदवारों के नाम थे। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा और वित्तमंत्री हरपाल चीमा का नाम शामिल नहीं था।

सोलापुर एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला ट्रेनिंग विमान, महिला पायलट सुरक्षित

सोलापुर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर बड़ा मामला सामने आया है। सोलापुर एयरपोर्ट पर एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रनवे से फिसल गया। इससे एयरपोर्ट के आसपास हड़कंप मच गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, टेकऑफ के लिए स्पीड बढ़ाते समय पायलट का विमान पर से नियंत्रण हट गया। इसके कारण विमान रनवे के किनारे से फिसल गया। गनीमत रही कि विमान में सवार महिला ट्रेनी पायलट सुरक्षित रहीं और एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल महिला ट्रेनी पायलट अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान टेकऑफ करने का प्रयास कर रही थीं। तभी विमान अचानक रनवे से उतर गया। इस अप्रत्याशित घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। हालांकि, पायलट के सुरक्षित होने का पता चलने पर सभी ने राहत की सांस ली इस घटना के पीछे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। क्या यह किसी तकनीकी खराबी, नियंत्रण खोने, या किसी अन्य कारण से हुआ? इसका पता आधिकारिक जांच के बाद ही चलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की बैठक ली

34 माह में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित, 28 जिलों के 13.56 लाख किसानों को दिन में मिल रही बिजली



जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 34 माह से अधिक के कार्यकाल में राजस्थान में बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को पर्याप्त विद्युत सप्लाई जारी रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से अन्य प्रदेशों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की बिजली विक्रय की गई है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने रबी सीजन में किसानों को दिन में दी जाने वाली बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में खैरथल-तिजारा में भी दिन में किसानों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिससे प्रदेश में अब कुल 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है तथा 13 लाख 56 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने राज्य में बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि बिजली में 31 मार्च 2023 को कुल घाटा 92,069 करोड़ रुपये था, जो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़कर 98,634 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में घाटे में 6,565 की वृद्धि दर्ज की गई, जो 9 माह में 7.13 प्रतिशत रही। इसी आधार पर वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित 9.50 प्रतिशत रहने से वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह घाटा 1 लाख 21 हजार 73 करोड़ रुपये पहुंच जाता। ऊर्जा विभाग ने इस घाटे को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह घाटा 89,907.77 करोड़ रुपये ही रहा। ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन के जरिए ऊर्जा क्षमताओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत छीजत में और अधिक कमी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के तीनों डिस्कॉम्स में कुल विद्युत छीजत 19.43 प्रतिशत थी, जो कि सुधारात्मक कदमों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 12.84 प्रतिशत रह गई है। वहीं, जोधपुर डिस्कॉम्स में वित्तीय वर्ष 2019-20 विद्युत छीजत लगभग 38 प्रतिशत थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 18.64 प्रतिशत हो गई है।

मुख्यमंत्री ने पीएम कुसुम योजना के घटक ए व सी के और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक घटक ए में 1,779 से अधिक मेगावाट एवं घटक सी में 3,758 से अधिक मेगावाट क्षमता स्थापित की है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय समान अवधि में घटक ए 9.5 मेगावाट व घटक सी शून्य क्षमता पर रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पीएम कुसुम योजना के घटक ए व सी में स्थापित क्षमता के आधार पर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

इससे 3 लाख 89 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

राजस्थान में विगत 34 माह में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार में इसी समान अवधि में अक्षय ऊर्जा क्षमता 5.9 गीगावाट ही स्थापित की गई थी। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के तय लक्ष्यों की प्राप्ति के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा स्थापना एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में दूसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस निर्णयों से जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हुई है। अजमेर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 825 करोड रुपये, 2024-25 में 1875 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जयपुर डिस्कॉम 931 करोड़ रुपये के लाभ में रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 34 माह में 400, 220, 132 केवी के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार इसी समान अवधि में 27 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित कर पाई थी। उन्होंने दिसंबर माह तक 16 नए ग्रिड सब-स्टेशनों के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर वीसी के माध्यम से जुड़े। वहीं, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा, शासन सचिव ऊर्जा विभाग आरती डोगरा सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बम धमाकों की धमकी से मुंबई में अलर्ट, ईमेल में कई ठिकानों का जिक्र

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में एक बार फिर बम धमाकों की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस बार धमकी भरे ईमेल में सिर्फ बैंक और एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि मेयर कार्यालय, अदालत, महालक्ष्मी रेसकोर्स, अभिनेता अमिताभ बच्चन का बंगला और गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रमों का भी जिक्र किया गया है। ईमेल मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच की गई। हालांकि, शुरूआती जांच के दौरान किसी भी जगह से कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक, 12 नवंबर को सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर एक ईमेल पते से धमकी भेजी गई।

यह ईमेल पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई जोनल कार्यालय, कफ परेड स्थित लोकल क्राइम ब्रांच और दक्षिण मुंबई के जवेरी बाजार स्थित बैंक शाखा को भेजा गया था। ईमेल में मुंबई के कई स्थानों पर बम धमाके और हमले करने की चेतावनी दी गई। नगर निगम का भी इसमें उल्लेख था, जिसके बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया गया। धमकी भरे ईमेल पर 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें इंजीनियर गुरनाख सिंह, रूकन शाहवाला और डॉ. गुरनिवैर सिंह खान राजादा के नाम भी लिखे गए थे। हालांकि, ईमेल में इन नामों और कथित संगठन का उल्लेख होने के बावजूद इसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईमेल भेजने वाले का इस संगठन से कोई संबंध है या नहीं। सुरक्षा एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की विश्वसनीयता की जांच कर रही हैं। ईमेल में अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' पर कार बम से हमला करने की धमकी दी गई। इसके अलावा गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का भी नाम लिया गया।

ईमेल में लोगों को उनके आगामी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई। महालक्ष्मी स्टेडियम का जिक्र करते हुए दिलजीत से जुड़ी धमकी लिखी गई थी। धमकी मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर सुरक्षा जांच और निरीक्षण किए गए। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान किसी भी जगह कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। सुरक्षा एजेंसियां अब ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की विश्वसनीयता की जांच कर रही हैं।

सरकारी खजाने में टैक्स बढ़ा

प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.42 लाख करोड़ के पार



नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की मजबूत आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन के दम पर चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह (डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक की अवधि में देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 फीसदी बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 12.90 लाख करोड़ रूपये रहा था। इस तेज रफ्तार के साथ सरकार ने पूरे साल के लिए तय बजट लक्ष्य का 53 फीसदी से अधिक हिस्सा नवंबर के पहले पखवाड़े में ही हासिल कर लिया है।

रिफंड जारी करने से पहले यानी ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी सालाना आधार पर मजबूत उछाल दर्ज किया गया है:

- सकल संग्रह (ग्रॉस कलेक्शन): रिफंड से पहले कुल ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 14.02 फीसदी बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रूपये दर्ज किया गया, जो बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 15.35 लाख करोड़ रूपये था।

- बजट लक्ष्य की स्थिति: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों से कुल 26.97 लाख करोड़ रूपये जुटाने का बजटीय लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्त वर्ष (2026) के 23.40 लाख करोड़ रूपये के संग्रह से 15 फीसदी अधिक है। लक्ष्य प्राप्ति: 10 नवंबर तक 14.42 लाख करोड़ रूपये की शुद्ध वसूली के साथ सरकार अपने कुल बजट लक्ष्य का लगभग 53 फीसदी मुकाम पार कर चुकी है।

टैक्स आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण से साफ है कि इस बढ़ोतरी का मुख्य आधार भारतीय कंपनियों की मजबूत आमदनी रही है:

- कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी छलांग: शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में लगभग 17.84 फीसदी का जोरदार इजाफा देखा गया। यह आंकड़ा पिछले साल के 5.36 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रूपये पहुंच गया।

- गैर-कॉरपोरेट टैक्स की चाल: व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों द्वारा चुकाए जाने वाले नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में 5.30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इस मद में संग्रह पिछले साल के 7.18 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रूपये रहा।

पूंजी बाजार में खुदरा और संस्थागत निवेशकों की भारी भागीदारी का सीधा फायदा टैक्स संग्रह में देखने को मिला है:

- एसटीटी में रिकॉर्ड उछाल: शेयर बाजार में होने वाले सौदों पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) संग्रह करीब 51.56 फीसदी उछलकर 54,077.90 करोड़ रूपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 35,681.88 करोड़ रूपये था।

- रिफंड में भी 26% की बढ़ोतरी: करदाताओं को रिफंड जारी करने की गति भी तेज बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक कुल टैक्स रिफंड 25.7 फीसदी (करीब 26%) बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रूपये रहा, जो पिछले साल समान अवधि में 2.45 लाख करोड़ रूपये था।

आगे राजकोषीय मोर्चे पर इसके क्या मायने हैं? चालू वित्त वर्ष के करीब सात महीनों में बजट के आधे से अधिक प्रत्यक्ष कर लक्ष्य का हासिल होना राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिहाज से सकारात्मक संकेत है। कॉरपोरेट टैक्स में लगभग 18 फीसदी की उछाल और शेयर बाजार से जुड़े एसटीटी संग्रह में 51 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्शाती है कि घरेलू कंपनियों की बैलेंस शीट और वित्तीय बाजार दोनों मजबूत स्थिति में हैं। आने वाले महीनों में अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की अगली किश्तों के बाद संग्रह की रफ्तार बजट अनुमानों को और मजबूती दे सकती है।

दिवाली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाए पुराने किस्से

कुर्सियां लगाने से प्रधानमंत्री बनने तक, मोदी ने सुनाया पत्रकारों से जुड़ाव का किस्सा



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली मिलन समारोह के दौरान मीडियाकर्मियों को छठ और दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद उनकी भूमिका और दायित्व बदल गए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार की जिम्मेदारियों और बदलती भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'त्यौहारों का समय ऐसा होता है, जब हर कोई अपने घर पर, अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करता है। लेकिन आपका काम ऐसा है कि ब्रेकिंग न्यूज के लिए भागदौड़ लगी रहती है। ऐसी व्यस्तता में आप सभी इस नॉन ब्रेकिंग न्यूज वाले कार्यक्रम में आए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित दिवाली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मेरा लंबे समय से आप सभी के साथ स्वाभाविक जुड़ाव रहा है। प्रेस विज्ञप्तियों से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक, मैंने मीडिया और उसके साथ संवाद के तरीके में लंबे समय के दौरान आए बदलावों को देखा है। मुझे याद है कि 1990 के दशक की शुरूआत में मुझे देशभर में निकाली गई दो बड़ी यात्राओं के दौरान संगठन की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। उस समय प्रेस विज्ञप्ति भेजने के लिए भी फैक्स मशीन ढूंढनी पड़ती थी। जब मैं दिल्ली आया, तब भी ये जिम्मेदारियां मेरे पास थीं। उन्होंने कहा, उस समय पार्टी का कार्यालय अशोक रोड पर हुआ करता था। तब भी दिवाली मिलन समारोह आयोजित होता था। इन कार्यक्रमों में मेरी जिम्मेदारी कुर्सियों का इंतजाम करने और आप सभी का ध्यान रखने की होती थी। मैं यही काम किया करता था। उस समय कैमरों की संख्या कम थी, लेकिन आपसी रिश्तों में वही अपनापन और नजदीकी बनी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली मिलन समारोह के दौरान अपने पत्रकार मित्रों से गुजरात का मुख्यमंत्री बनने की खबर मिलने का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, पिछले महीने मुझे सरकार का प्रमुख बने हुए 25 साल पूरे हो गए। मुझे यह घटना बहुत अच्छी तरह याद है। आज भी मैं सोचता हूं कि आप लोगों में ऐसा क्या है, जो हमें हमेशा चौंका देता है।

उन्होंने कहा, उस समय इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। पार्टी के सिर्फ दो-चार वरिष्ठ नेताओं को ही पता था। मैं अपना ज्यादातर समय यहां 11 अशोक रोड पर बिताता था। एक दिन पत्रकारों का पूरा समूह मेरे कमरे में आ गया। आमतौर पर पत्रकार मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे, लेकिन उस दिन वे सीधे कमरे में चले आए। प्र.म. ने कहा, उनके बीच महिला पत्रकारों का एक समूह भी था, जिसका काफी प्रभाव था। उन्होंने मुझसे कहा, आपको हमें मिठाई खिलानी होगी। मैंने पूछा, किस बात की खुशी में? मैं मिठाई क्यों बांटू? उन्होंने जवाब दिया, आप गुजरात जा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।

भाजपा का संकल्प गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं से सुसज्जित करना: राठौड़



जयपुर (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य गांवों को केवल विकास योजनाओं का लाभ देना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सुविधासंपन्न और विकसित ग्राम बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पष्ट विजन के साथ काम किया है। भाजपा की ओर से गांवों के विकास के लिए 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' जारी कर ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जनता के सामने रखा है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित कर 'शहर ग्राम' की अवधारणा को साकार किया जाए। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच वर्षों में औसतन पांच करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए 25 लाख आवासीय पट्टे वितरित करने, 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 19 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें बनाने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 हजार किलोमीटर से अधिक नई सड़कें विकसित करने का संकल्प किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान स्थापित करें। किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान को केंद्र में रखकर किए जा रहे ये प्रयास विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर 8 से 25 दिसंबर तक प्रदेशभर में कार्यक्रम प्रस्तावित

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 8 से 25 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को प्रमुख आयोजनों में से एक बताया और कहा कि इस बार युवाओं के लिए नई गतिविधियां और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं भी कार्यक्रमों में शामिल की गई हैं। तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में प्रस्तावित है। इसमें कृषि निवेश और निर्यात की संभावनाओं, बागवानी, मोटे अनाज, खेती की नई तकनीकों और जल संरक्षण पर चर्चा होगी। युवाओं के लिए नवाचार सम्मेलन के साथ खेलो राजस्थान, शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं शुरू करने की योजना है। राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव एवं कौशल मेला, नारी शक्ति सम्मेलन और राष्ट्रीय सरस मेला भी प्रस्तावित कार्यक्रमों में शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों में शिविर लगाने की योजना है। शेखावाटी हेरिटेज मीट और प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के साथ जैसलमेर में पर्यटन सम्मेलन और लोक कला उत्सव का शुभारंभ प्रस्तावित है।

दैनिक लोकजीवन
जयपुर एवं भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित
संरक्षक - स्व. डॉ. रिजकुमार जी डिडवी

पाकिस्तान की कमजोर होती बुनियाद, बढ़ती आंतरिक चुनौतियां

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की कुल 53 सीटें हैं। इनमें स्थानीय लोगों के लिए 33 सीटें, 12 शरणार्थी सीटें और महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स, मौलवियों तथा विदेश में रहने वाले यहां के लोगों के लिए आठ आरक्षित सीटें हैं। शरणार्थी सीटों से आशय उन सीटों से है, जो कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग से आए। अजीब बात यह है कि ये शरणार्थी यहां के निवासी न होकर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में इनकी सहभागिता से स्थानीय निवासियों और अन्य हिस्सों के लोगों के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। शरणार्थी सीटों में मतदाताओं की संख्या बहुत कम है और वे बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। इससे पाकिस्तानी सरकार के लिए चुनाव परिणामों में हेरफेर करना आसान हो जाता है और हर चुनाव में अधिकांश सीटों पर उसी दल की ही जीत होती है, जिसे पाकिस्तानी शासक जिताना चाहते हैं। ये चुनाव क्षेत्र कितने छोटे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल के चुनावों में एलए-43 निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,839 ही थी, जबकि अधिकतम मतदाताओं वाली एलए 45 सीट पर 4,271 ही मतदाता थे। इन सीटों की बदौलत पाकिस्तान सरकार को इस प्रांत की विधानसभा में 25 प्रतिशत की एकमुश्त वोटिंग मिल जाती है, जो सत्ता की चाबी अपने पास रखने में मददगार बनती है।

प्रांतीय सरकार ने शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरणार्थी सीटें प्रांतीय संविधान द्वारा ही तय की गई हैं और उन्हें संविधान में परिवर्तन के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन में न पाकिस्तान को, न ही प्रांत की कठपुतली सरकार को कोई रूचि है। जो सरकार शरणार्थी सीटों के बल पर ही अस्तित्व में आई हो, वह भला इन सीटों को क्यों खत्म करेगी? इन चुनावों में प्र.म.एल-एन ने 31 सीटें जीतकर 53 सीटों के सदन में बहुमत हासिल किया। इनमें से 11 सीटें शरणार्थी सीटें हैं। उनके बिना उसका बहुमत ही खत्म हो जाएगा। अब गुलाम जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय दलों की कोई हैसियत नहीं बची, जबकि दशकों तक क्षेत्रीय दल ही यहां की सत्ता पर काबिज रहे।

पाकिस्तान के एक और अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर रूल घोषित कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि प्रांतीय सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ है और वहां बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों से न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे पाकिस्तान को खतरा है। इस प्रांत में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सत्ता में है और वह उनकी रिहाई के लिए अभियान छेड़े हुए है। देखना यह है कि राष्ट्रपति के फैसले से वहां इमरान खान के पक्ष में मुहिम कमजोर पड़ती है या उनके प्रति समर्थन और बढ़ता है? इस प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच हाल में तनातनी बढ़ी है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की सरकार उसके यहां अशांति फैला रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को शह दे रही है। पाकिस्तानी सेना एक सीमा से अधिक यहां सख्ती भी नहीं कर सकती, क्योंकि फौज में पठानों की संख्या काफी अधिक है।

पाकिस्तान के समक्ष मुश्किलें तब बढ़ रही हैं, जब वह कर्ज के बोझ से कराह रहा है। पाकिस्तानी रूपया डालर के सामने दम तोड़ता जा रहा है, जिससे उसकी आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिन हो रही है। केंद्र सरकार नए खर्चों के लिए पूरी तरह कर्जे पर निर्भर होती जा रही है, क्योंकि राजस्व के स्रोत सिकुड़ रहे हैं। इस सबके बाद भी वह अपनी भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के अघोषित शासक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर कितने ही प्रयास करें, लेकिन वे इस वास्तविकता को तो ओझल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की बुनियाद कमजोर हो रही है और वह खोखला होता जा रहा है। पिछले कुछ समय से ट्रंप की खुशामद कर रहे मुनीर के लिए शायद अब अमेरिकी राष्ट्रपति की चापलूसी भी काम न आए, क्योंकि मध्यावधि चुनाव के बाद खुद उनकी राह कठिन हो गई है। तमाम चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों से गुलाम जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग विधानसभा में 'शरणार्थी सीटों' को खत्म करने की है। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान इन सीटों का इस्तेमाल मुजफ्फराबाद की स्थानीय सरकार में अपने पिट्ठुओं को बिठाने के लिए करता आया है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी का गठन किया, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में जेएएसी ने 12वीं विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया। ऐसे माहौल में हुए चुनावों की कोई वैधता नहीं। जैसी उम्मीद थी, इन चुनावों में सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (प्र.म.एल-एन) की जीत हुई।

मतदाता सूची का शुद्धीकरण लोकतंत्र की संवैधानिक जरूरत

प्रत्येक वैध भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार मिले, प्रत्येक मतदाता केवल एक ही स्थान पर अपने मताधिकार का उपयोग करे और अवैध अथवा अनैतिक तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को देश की सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त न हो, इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 324, 325 और 326 में प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद मतदाता सूची के निर्माण, संशोधन और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दौरान एक संवैधानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक (एसआरएओ से बीएलओ तक) सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे विधानसभा स्तर से लेकर बूथ स्तर तक (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर इस प्रक्रिया में सहयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। फार्म 6, 7 और 8 का उपयोग करते हुए, मतदाता सूची के शुद्धीकरण में अपनी भूमिका निभाएं। गलत नाम जुड़ने या कटने पर वे आपत्ति दर्ज कराएं, लेकिन कमजोर राजनीतिक दल सभी बूथों पर अपने बीएलए-2 नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए वे वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस बिहार के 77,895 बूथों में से केवल 17,000 बूथों पर और बंगाल के 85,379 बूथों में से केवल 5,797 बूथों पर ही अपने बूथ एजेंट नियुक्त कर पाई थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार, कांग्रेस ने मतदाता सूची के संबंध में एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जिन राज्यों में एनडीए की सरकार बनी, वहां विपक्षी दलों के विधायक भी चुनाव जीते हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी दलों की सरकारें भी बनी हैं। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने एसआईआर की प्रशंसा भी की है। ऐसे में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करना लोकतंत्र के प्रति गंभीर अपराध है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में पहले आम चुनाव के बाद मतदाता सूची के शुद्धीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए 12 फरवरी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि 'सबसे पहले मतदाता सूची का शुद्धीकरण किया जाए।' केरल के नेता रमेश चेन्नीतला ने चुनाव आयोग को चार लाख अवैध मतदाताओं की सूची सौंपते समय कहा था कि भौतिक सत्यापन और मतदाता सूची के गहन शुद्धीकरण के बिना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है।

केरल में कांग्रेस अपनी जीत का श्रेय भी एसआईआर की प्रक्रिया को ही देती है। चुनाव आयोग केवल मतदान कराने वाली मशीन नहीं, बल्कि निष्पक्षता का प्रतीक है। विपक्ष के पास ठोस तथ्य हैं, तो उन्हें प्रमाण के साथ सुप्रीम कोर्ट में सामने लाना चाहिए। 'वोट चोरी' जैसे मुद्दे और प्रभावशाली शब्दों से जनता के मन में संदेह पैदा किया जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक बहस को मजबूती नहीं दी जा सकती। लोकतंत्र में आलोचना और अराजकता के बीच एक महीन रेखा होती है। उस रेखा को पार करने से लोकतांत्रिक लाभ नहीं, बल्कि अविश्वास बढ़ता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि 'हम भारत के लोग' अपने संविधान को आत्मार्पित करते हैं। यहाँ भारत में जन्मे, भारत की एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा रखने वाले और संविधान में आस्था रखने वाले नागरिकों से ही 'हम भारत के लोग' का तात्पर्य है। चुनाव, प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार और कानून का शासन लोकतंत्र के आधार हैं। भारत के प्रति समर्पित वयस्क नागरिकों को ही देश में सरकार चुनने का अधिकार है। चुनाव के माध्यम से भारत में राज्य और केंद्र की सरकारें चुनने का अधिकार विदेशी घुसपैठियों को देना कैसे संभव हो सकता है? इसी कारण संविधान में मतदाता सूची के शुद्धीकरण की व्यवस्था है।

भारतीय संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। इसके अंतर्गत अब तक चुनाव आयोग द्वारा 13 बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा चुका है। यह प्रक्रिया वर्ष 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में हुई है। वर्ष 2025 में बिहार से शुरू हुआ यह 14वां एसआईआर है। वर्ष 2004 से 22 वर्षों के दौरान यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में एसआईआर का विरोध करने वाले दलों की केंद्र और राज्यों में सरकारें रहते हुए भी कई बार मतदाता सूची के शुद्धीकरण की यह प्रक्रिया हुई है। संविधान का अनुच्छेद 326 मताधिकार को केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित करता है, जबकि अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने का दायित्व निर्वाचन आयोग को सौंपता है। यही मतदाता सूची के शुद्धीकरण की संवैधानिक व्यवस्था का आधार है।

प्रत्येक वैध भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार मिले, प्रत्येक मतदाता केवल एक ही स्थान पर अपने मताधिकार का उपयोग करे और अवैध अथवा अनैतिक तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को देश की सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त न हो, इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 324, 325 और 326 में प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद मतदाता सूची के निर्माण, संशोधन और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

आजीविका के उद्देश्य से अनेक नागरिक अपने मूल स्थान से दूसरे स्थानों पर प्रवास करते हैं। इसके कारण कई बार उनका नाम पुराने स्थान की मतदाता सूची में बना रहता है और वे नए स्थान पर भी अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में लगभग 45 करोड़ लोगों ने आंतरिक प्रवास किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, 2001 से 2011 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 50 से 65 लाख लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास किया। एसआईआर के अंतर्गत बिहार में 7.01 लाख ऐसे मतदाता पाए गए, जिनके नाम दो स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज थे। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में दर्ज नामों के सत्यापन के बाद करीब 13.30 करोड़ नामों में से दो करोड़ 80 लाख मृतकों के पाए गए। लगभग 6.30 करोड़ मतदाताओं ने अपना स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया था। करीब तीन करोड़ मतदाताओं के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। ये वही मतदाता हैं, जो भारत में वैध नागरिक न होते हुए भी भारत में सरकार चुनने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1.02 लाख मतदाताओं के नाम दो बार मतदाता सूची में दर्ज पाए गए। सेना के अवकाश प्राप्त जनरल एसके सिन्हा ने असम का राज्यपाल रहते हुए 8 नवंबर, 1998 को तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट 'रिपोर्ट आन इलीगल माइग्रेशन इनटू असम' में घुसपैठ के खतरे के संबंध में सचेत किया था। उनके अनुमान के अनुसार, तब केवल असम में ही 60 लाख घुसपैठिए थे। उन्होंने घुसपैठ और उग्रवाद के परस्पर संबंध तथा सीमा पर हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। वर्ष 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में जानकारी देते हुए बताया था कि लगभग दो करोड़ से अधिक घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। कुछ अनुमानों में यह संख्या तीन करोड़ तक बताई जाती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की विजय के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के स्वत: ही बांग्लादेश जाने की खबरें भी सामने आई थीं। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर की ओर जाते समय इन लोगों ने स्वीकार किया था कि उनके बिचौलियों और कुछ सत्तालोलुप नेताओं ने अवैध रूप से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवाए थे। कलकत्ता और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में भी इस तरह के तथ्य सामने आ चुके हैं। विपक्ष द्वारा एसआईआर का विरोध करने के पीछे अवैध घुसपैठियों के समर्थन की मंशा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वे उनके थोक मतदाता थे। क्या इनके बल पर ही विपक्षी दल चुनाव जीतते थे? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देश को देना चाहिए।

दिल्ली के प्रदूषण पर आखिर कब टूटेगी प्रशासनिक बेबसी

दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को दूर करने में मिल रही नाकामी 'ज्यादा जोगी, मठ उजाड़' या 'टू मेनी कुक्स स्पॉयल द ब्रोथ' की उक्ति चरितार्थ कर रही है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के नाते यह माना जाता था कि केंद्र और दिल्ली सरकार में सहयोग की कमी के कारण प्रदूषण के खिलाफ ठोस रणनीति नहीं बन पा रही है, लेकिन बीते एक वर्ष में तो ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है।

अब यह दलील भी नहीं चलने वाली कि पड़ोसी राज्यों की भिन्न दलों की सरकारें दिल्ली या केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही हैं, क्योंकि अब सभी सीमावर्ती राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। साफ है कि इच्छाशक्ति के अभाव का दुष्परिणाम ही है दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण।

इस दीवाली पर प्रधानमंत्री उस बस्तर में सीआरपीएफ जवानों के बीच थे, जो अभी हाल तक माओवादियों का गढ़ था। आज से 10-15 वर्ष पहले यह सोचना भी कठिन था कि बस्तर जैसा माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ उनके आतंक से मुक्त हो सकता है, पर ऐसा हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह संभव हो पाया 2019 में केंद्रीय गृहमंत्री बने अमित शाह की प्रबल इच्छाशक्ति से। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने माओवादी आतंक को एक समयसीमा देकर खत्म करने की ठानी और अंतत: इसमें सफल रहे।

विकट और पुरानी समस्याओं के समाधान में दृढ़ इच्छाशक्ति कैसे सहायक बनती है, इसका एक उदाहरण जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति भी है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण गोरखपुर और आसपास यानी पूर्वांचल में प्रति वर्ष जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक्यूट इनसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी इनसेफ्लाइटिस (जेई) से बड़ी संख्या में होने वाली मौतों का सिलसिला थमाना भी है। यह योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छाशक्ति से संभव हो सका। उन्होंने इस समस्या से मुक्ति पाने का अभियान अपने हाथ में तभी ले लिया था, जब वे गोरखपुर के सांसद मात्र थे। उन्होंने इस समस्या को बार-बार संसद में उठाने के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य



मंत्रालय को इसके लिए बाध्य किया कि वह पूर्वांचल को इस त्रासदी से बचाने के लिए कुछ विशेष उपाय करे। उनके प्रयासों से गोरखपुर के मेडिकल कालेज को ऐसी सुविधाओं से लैस किया गया, जिससे एईएस और जेई की पहचान और उपचार में आसानी हो। बच्चों के लिए प्राय: जानलेवा सिद्ध होने वाली इन रोगों से पार पाना आसान न था, क्योंकि उनका प्रकोप पूर्वांचल के सात जिलों में फैला था। इन संचारी रोगों की चपेट में आने वाले अधिकतर मरीजों के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज ही एक बड़ा सहारा था। एक वक्त हर साल सैकड़ों बच्चे इन रोगों के शिकार होकर दम तोड़ देते थे। चूंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल को इस विकट संकट से मुक्ति दिलाने में प्राणपण से जुटे, इसलिए उनके प्रयासों से एईएस और जेई का प्रकोप तभी कम होना शुरू हो गया, जब दिल्ली-लखनऊ, कहीं भी भाजपा सत्ता में नहीं थीं। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आने और 2017 में योगी के स्वयं उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद एईएस और जेई से लड़ने की रणनीति अधिक प्रभावी हुई। इस रणनीति के तहत यूनिसेफ की मदद से 'दरवाजा खटखटाओ-एईएस और जेई भगाओ' नारे के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया।

सभी प्रभावित जिलों में बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस समस्या का सामना केवल स्वास्थ्य विभाग से संभव नहीं था, इसलिए गंदगी हटाने, पेयजल की गुणवत्ता सुधारने आदि के लिए ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पंचायती राज सहित करीब दस विभागों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास किए गए।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की तरह प्रशासनिक इच्छाशक्ति भी विकट समस्याओं का समाधान आसान करती है। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाली खान-पान की सामग्री बनाने-बेचने वालों पर सख्ती दिखना। यह संभव हो पाया राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे की सख्ती से। ऐसे नेता और नौकरशाह और भी हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से लोगों को जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाई। यदि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का संयोग हो जाए तो समस्याओं का समाधान और आसान हो जाता है, लेकिन कई बार नेता और नौकरशाह मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते और इसका ही एक उदाहरण है दिल्ली-एनसीआर का बढ़ता वायु प्रदूषण। हालांकि दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण की चर्चा सबसे अधिक होती है, पर सच यह है कि अब इस प्रदूषण ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। न तो दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण दूर हो पा रहा है और न ही शेष उत्तर भारत का। यह तब है, जब दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनकी तमाम एजेंसियों, समितियों के साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के साथ सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय हैं।

जब इन सबकी सक्रियता के बाद भी दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण दूर होने का नाम नहीं ले रहा तो इसके आसार कम ही हैं कि शेष उत्तर भारत का शासन-प्रशासन उससे पार पा पाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने साईपुरा के मतदान केंद्र एवं आंधी के संग्रहण केंद्र का किया निरीक्षण

चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा स्ट्रांग रूम सहित अन्य व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश

जयपुर (कासं)। पंचायतीराज आम चुनाव के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक एवं पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण हनुमान प्रसाद मीना ने गुरुवार को पंचायत समिति जमवारामगढ़ एवं पंचायत समिति आंधी में चुनावी तैयारियों तथा कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्राम पंचायत साईपुरा के मतदान केंद्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात उपखंड अधिकारी कार्यालय, जमवारामगढ़ में रिटर्निंग अधिकारी जमवारामगढ़, रिटर्निंग अधिकारी आंधी, पुलिस अधिकारियों, विकास अधिकारी जमवारामगढ़ एवं आंधी तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ एवं आंधी के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव तैयारियों, मतदान दलों के प्रशिक्षण एवं रवानगी, मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करें। मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं तथा संवेदनशील मतदान



केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत समिति आंधी के संग्रहण केंद्र पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंधी का भी निरीक्षण किया। यहां मतदान के उपरांत ईवीएम एवं मतदान सामग्री का संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने संग्रहण केंद्र पर स्ट्रांग रूम, काउंटर, सुरक्षा, प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा ईवीएम की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं होने देने के निर्देश दिए।

इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी जमवारामगढ़ ओम प्रकाश मीणा, रिटर्निंग अधिकारी आंधी सुप्रिया कालेर, पुलिस उपाधीक्षक जमवारामगढ़ राम किशन विश्नोई, विकास अधिकारी जमवारामगढ़ एवं आंधी तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ एवं आंधी उपस्थित रहे।

सांस अभियान के तहत जयपुर प्रथम में बाल स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर

28 फरवरी 2027 तक घर-घर पहुंचकर पांच वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया की पहचान, बचाव एवं समय पर उपचार के लिए चलेंगा विशेष जागरूकता गतिविधियां

जयपुर। पांच वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाने, समय पर लक्षणों की पहचान, समुचित उपचार एवं आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थान में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जयपुर प्रथम जिले में 12 नवंबर 2026 से सांस अभियान के तहत विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी। यह अभियान आगामी 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इसके साथ ही 15 से 21 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन भी किया जाएगा। दोनों कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नवजात एवं पांच वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि सांस अभियान के अंतर्गत जिले में शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया के लक्षणों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार और गंभीर स्थिति में उच्च चिकित्सा संस्थान तक भेजने पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंगकर्मियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों को अभियान की गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

अभियान के दौरान आशा सहयोगिनियों द्वारा नियमित रूप से घर-घर जाकर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया के लक्षणों की पहचान



की जाएगी। बच्चों में खांसी, तेज सांस चलना, छाती में धंसाव, सांस लेने में परेशानी तथा दूध या अन्य तरल पदार्थ पीने में असमर्थता जैसे लक्षणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संभावित निमोनिया से ग्रसित बच्चों को निर्धारित उपचार पद्धति के अनुसार उपचार उपलब्ध करवाने के साथ आवश्यकता होने पर उच्च चिकित्सा संस्थान में भेजा जाएगा। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. महेश चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में निमोनिया के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों, ऑक्सीजन एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप जिला अस्पतालों में निमोनिया से ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। अभियान के प्रमुख घटक रोकथाम, सुरक्षा एवं उपचार के तहत बच्चों में निमोनिया की रोकथाम और उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पेंटावेलेंट एवं न्यूमोकोकल टीके की सभी निर्धारित खुराक सुनिश्चित करने के साथ बच्चों के नियमित टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, 15 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के दौरान नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल, स्तनपान को प्रोत्साहन, नवजात संक्रमणों की रोकथाम, समय पर स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक किया जाएगा। 'स्माल बेबीज़, बिग पोटेंशियल' थीम पर आयोजित होने वाले इस सप्ताह में स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से नवजात शिशुओं की देखभाल एवं उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 'स्वास्थ्य विभाग की अपील' अभिभावक बच्चों में खांसी, तेज सांस चलने, छाती में धंसाव या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल करें तथा नियमित टीकाकरण अवश्य करवाएं। समय पर पहचान, उचित उपचार और जागरूकता से बच्चों को निमोनिया के गंभीर परिणामों से बचाया जा सकता है।

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित बच्चे का सफल इलाज

एक प्रमुख बाल चिकित्सा और प्रसूति अस्पताल, मधुकर रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित एक बच्चे का सफल इलाज किया है। एसएमए एक जन्मजात आनुवंशिक विकार है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इस मामले में 3-4 महीने की उम्र से ही शिशु के ऊपरी और निचले दोनों अंगों में लगातार कमजोरी आ रही थी। साथ ही श्वसन मांसपेशियों की कमजोरी के कारण सांस लेने में कठिनाई बढ़ रही थी। ऐसे मामलों में बच्चे के 2-3 साल से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं होती है।

यह जन्मजात आनुवंशिक विकार है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है

न्यूरोलॉजी टीम ने मुंह से दी जाने वाली दवा दी जो जीन संशोधित दवा थी। माता-पिता को घर पर दवा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त पल्मोनोलॉजी टीम ने माता-पिता को उचित भोजन के तरीके और वायुमार्ग प्रबंधन तकनीकों के बारे में बताया। बच्चे की हालत में काफी सुधार हुआ और उसकी सांस संबंधी समस्याएं ठीक हो गई। बेहतर मांसपेशियों की शक्ति के कारण वह लंबे समय तक बैठने में भी सक्षम हो गया है। दवा के बिना ऐसा नहीं हो सकता था।

डॉ. चंद्र शेखर सिंघा, वरिष्ठ सलाहकार, एमडी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, ने कहा, 'आनुवंशिक विकार उपचार प्रभावी है लेकिन इसकी उच्च लागत विकासशील देशों में इस तक पहुंच को मुश्किल बनाती है। इन मामलों में वाहक स्क्रीनिंग और प्रसवपूर्व निदान जैसी पारंपरिक आनुवंशिक विधियाँ आवश्यक हो जाती है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. रेखा मित्तल ने कहा, 'अनुसंधान में निवेश करना, उपचार की लागत कम करना और सामान्य आबादी में अधिक जागरूकता बढ़ाना वास्तव में समय की जरूरत है।

पीठ दर्द



मस्तिष्क से उत्पन्न होता है तो तेजी से ठीक होने में मदद मिल सकती है

पुराने पीठ दर्द से पीड़ित अधिकांश लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि उनका दर्द चोट या शरीर में अन्य समस्याओं जैसे गठिया या उभरी हुई डिस्क के कारण होता है। लेकिन एक शोध टीम ने पाया है कि मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया के रूप में दर्द के मूल कारण के बारे में सोचने से रिकवरी को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यह एक नए अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष है, जो हाल ही में एक मासिक ओपन-एक्सेस मेडिकल जर्नल जेएएमए नेटवर्क ओपन में प्रकाशित हुआ। टीम ने दर्द पुनर्संसाधन थेरेपी नामक एक मनोवैज्ञानिक उपचार का अध्ययन किया जो मस्तिष्क में अप्रभावी और अनावश्यक दर्द संकेतों को 'बंद' करने में मदद कर सकता है। ऐसा करने के लिए, एक नया अध्ययन किया गया जिसमें कुछ लोगों को दर्द निवारण थेरेपी उपचार प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना गया, जबकि कुछ को उनकी पीठ में प्लेसबो इंजेक्शन दिया गया।

पुराने पीठ दर्द से पीड़ित 21 से 70 वर्ष की उम्र के 151 वयस्कों में पाया गया कि 66% प्रतिभागियों ने दर्द पुनर्प्रसंस्करण थेरेपी के बाद दर्द-मुक्त या लगभग दर्द-मुक्त होने की बात कही, जबकि प्लेसबो प्राप्त करने वाले 20% लोगों ने ऐसा कहा। ये परिणाम उल्लेखनीय थे क्योंकि मनोवैज्ञानिक उपचारों के पिछले परीक्षणों में शायद ही कभी लोगों ने पुराने दर्द से पूरी तरह ठीक होने की सूचना दी हो। इसलिए यह बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है कि यह उपचार कैसे काम करता है : लोगों की सोच में ऐसा क्या बदलाव आया जिससे उन्हें पुराने पीठ दर्द से उबरने में मदद मिली?

यह क्यों मायने रखता है

पुराने समय से चला आ रहा दर्द आज सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह अमेरिका में विकलांगता का प्रमुख कारण है, और इसकी आर्थिक लागत मधुमेह या कैंसर से भी अधिक है। सबसे आम दीर्घकालिक दर्द पीठ दर्द है। कई मरीज़ - और डॉक्टर - पीठ की विभिन्न समस्याओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें संदेह है कि यह दर्द का कारण हो सकता है। इसलिए वे हर तरह के उपचार आज़माते हैं, लेकिन अक्सर कोई फायदा नहीं होता। वैज्ञानिकों की बढ़ती संख्या अब यह मानती है कि पुराने पीठ दर्द के कई मामले मुख्य रूप से मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण होते हैं। दर्द किसी चोट से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन फिर दर्द प्रणाली वहीं 'अटक' सकती है और चोटें ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक दर्द जारी रख सकती है।

दर्द मस्तिष्क का अलार्म सिस्टम है, जो हमें हमारे शरीर पर चोट या अन्य खतरों के बारे में बताता है। अधिकांश समय, यह सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, हमें सटीक रूप से चेतावनी देता है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा घायल हो गया है और उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति महीनों, वर्षों या दशकों तक दर्द में रहता है, तो दर्द प्रसंस्करण मार्ग के अपना काम ठीक से नहीं करने की संभावना बढ़ जाती है, और मस्तिष्क क्षेत्र जो आमतौर पर दर्द में शामिल नहीं होते हैं, वे इसमें शामिल होने लगते हैं। क्रोनिक दर्द से ग्लियाल कोशिकाओं में गतिविधि का स्तर भी बढ़ जाता है, जो मस्तिष्क की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। मस्तिष्क में होने वाले ये सभी परिवर्तन दर्द को 'गहरा' करने का काम करते हैं, जिससे यह बना रहता है। लोग, बहुत स्वाभाविक रूप से, सोचते हैं कि यदि उनकी पीठ में दर्द होता है, तो पीठ में कोई समस्या होगी - भले ही शोधकर्ता जानते हैं कि अक्सर ऐसा नहीं होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि संकेत मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, दर्द कम वास्तविक नहीं है। दर्द हमेशा वास्तविक होता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसका प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए, मूल कारण की सटीक पहचान करना आवश्यक है।

हम अपना काम कैसे करते हैं

अध्ययन में, लोगों से अपने शब्दों में यह बताने के लिए कहा गया कि वे क्या सोचते हैं कि उनके पुराने पीठ दर्द का कारण क्या है। यह एक सरल प्रश्न है, लेकिन कुछ अध्ययनों ने अपने प्रतिभागियों से उनके दर्द के स्रोत का वर्णन करने के लिए कहा। अध्ययन में प्रतिभागियों ने चोटों, कमजोर मांसपेशियों, गठिया और अन्य शारीरिक कारकों को अपने दर्द का कारण बताया। लगभग किसी ने भी मन या मस्तिष्क के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। दर्द पुनर्संसाधन चिकित्सा का एक मुख्य लक्ष्य लोगों को उनके दर्द के कारणों के बारे में अलग ढंग से सोचने में मदद करना है। जब हमने प्रतिभागियों का दर्द पुनर्प्रसंस्करण थेरेपी से इलाज किया, तो लोगों द्वारा बताए गए दर्द के लगभग आधे कारण मन या मस्तिष्क से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि 'चिंता', 'भय' या 'तंत्रिका मार्ग' जैसी चीजें उनके दर्द का कारण थीं। जितना अधिक लोग यह बात समझते गए, उतना ही अधिक उनका पीठ दर्द कम होता गया। समझ में यह बदलाव भय और दर्द से बचाव को कम करता है, जो मस्तिष्क में दर्द के मार्गों को कम कर सकता है और व्यायाम और सामाजिककरण जैसे स्वस्थ, दर्द कम करने वाले व्यवहारों को बढावा दे सकता है। दर्द के अंतर्निहित कारणों की सटीक पहचान करना इसे ठीक करने की दिशा में पहला कदम है।

गूगल प्ले

बताएगा, वीपीएन ऐप सुरक्षित है या नहीं



वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) ऐप्स से शुरुआत करते हुए, गूगल प्ले स्टोर पर कुछ श्रेणियां अब यूजरों को भरोसेमंद और सुरक्षित ऐप्स ढूंढने में मदद करने के लिए एक बैनर दिखाएंगी। गूगल ने कहा कि ये बैनर यूजरों को स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा बैज के बारे में बताएंगे, उन ऐप्स को उजागर करेंगे जिनका स्वतंत्र ऑडिट हुआ है। कंपनी ने कहा, यूजरों को एक सरल व्यू देने में मदद करने के लिए कि कौन से ऐप्स स्वतंत्र सुरक्षा सत्यापन से गुजरे हैं, हम विशिष्ट ऐप प्रकारों के लिए एक नया गूगल प्ले स्टोर बैनर पेश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत वीपीएन ऐप्स से होगी। जब कोई यूजर वीपीएन ऐप खोजता है, तो उसे अब गूगल प्ले के शीर्ष पर एक बैनर दिखाई देगा जो उसे डेटा सुरक्षा अनुभाग में स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा बैज के बारे में जानकारी देगा। यूजरों के पास और जानें को चुनने का विकल्प भी है, जो उन्हें ऐप वैलिडेशन डायरेक्टरी पर रीडायरेक्ट करता है, जो उन सभी वीपीएन ऐप्स को देखने के लिए एक केंद्रीकृत स्थान है जिनकी स्वतंत्र रूप से सुरक्षा समीक्षा की गई है। गूगल ने कहा, यूजर ऐप वैलिडेशन डायरेक्टरी में अतिरिक्त तकनीकी मूल्यांकन विवरण भी खोज सकते हैं, जिससे उन्हें वीपीएन ऐप को डाउनलोड करने, उपयोग करने और अपने डेटा पर भरोसा करने के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। वीपीएन प्रदाता जैसे नॉर्डवीपीएन, गूगल वन, एक्सप्रेस वीपीएन और अन्य पहले ही स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण से गुजर चुके हैं और सार्वजनिक रूप से बैज घोषित कर चुके हैं। कंपनी ने कहा, हम अतिरिक्त वीपीएन ऐप डेवलपर्स को स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।



कनाडा में पार्लियामेंट हिल पर दिवाली समारोह मनाया गया

इंडो-कनाडाई सांसद चंद्रा आर्य द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में भारतीय प्रवासियों के प्रमुख सदस्यों ने पार्लियामेंट हिल पर पवित्र प्रतीक 'ओम' के साथ एक हिंदू ध्वज भी फहराया। रविवार को मनाया गया समारोह कनाडा में चल रहे हिंदू विरासत माह के साथ मेल खाता है, जो समुदाय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के लिए हर साल नवम्बर में आयोजित किया जाता है। आर्य ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में लिखा, मुझे पार्लियामेंट हिल पर दिवाली की मेजबानी करने में खुशी हुई।

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों, स्वयंसेवकों और उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को मेरा हार्दिक धन्यवाद। इस आयोजन को 67 हिंदू और इंडो-कनाडाई संगठनों का समर्थन प्राप्त था और इसमें ओटावा, ग्रेटर टोरंटो एरिया और मॉन्ट्रियल सहित देश भर से प्रतिभागियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के सांसद आर्य ने पिछले महीने देश के पार्लियामेंट हिल में पहली बार हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा की मेजबानी भी की थी। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में इस साल खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मद्देनजर भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण राजनयिक गतिरोध के बावजूद यह जश्न मनाया गया। आर्य हिंदुओं को निशाना बनाने वाली घृणा अपराध की घटनाओं के मुखर आलोचक रहे हैं, और उन्होंने खालिस्तान समर्थकों द्वारा मंदिरों और भारतीय प्रतिष्ठानों पर हाल के हमलों की कड़ी आलोचना की है और कार्रवाई की मांग की है।

■ इस आयोजन को 67 हिंदू और इंडो-कनाडाई संगठनों का समर्थन प्राप्त था और इसमें ओटावा, ग्रेटर टोरंटो एरिया और मॉन्ट्रियल सहित देश भर से प्रतिभागियों ने भाग लिया

'देवरानी जेठानी 2' का फर्स्ट लुक रिलीज

भोजपुरी सिनेमा की जानीमानी अभिनेत्री अंजना सिंह और संचिता बनर्जी की आने वाली फिल्म देवरानी जेठानी 2 फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। जिसमें फिल्म की लीड अभिनेत्री अंजना सिंह और संचिता बनर्जी एक दूसरे के साथ उलझती नजर आ रही है। वहीं दूसरी और उनके पति की भूमिका में गौरव झा और देव सिंह एक दूसरे को झगड़े से अलग करते दिखाई दे रहे है। इस फिल्म को अजय कुमार झा ने निर्देशित किया है। फिल्म के निर्माता प्रदीप सिंह के साथ अपूर्व मेड़तिया, मोनिका सिंह और प्रतीक सिंह है।

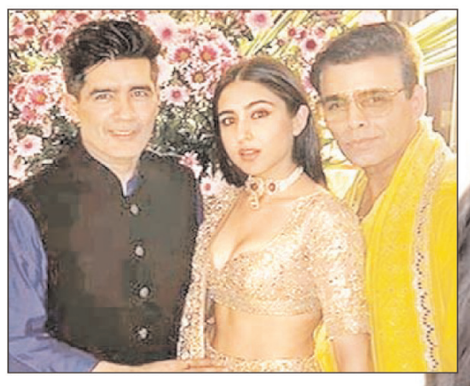
कलर्स का नया शो डोरी शुरू

कलर्स ने अपने नए फिक्शन शो डोरी को शुरू करके बालिका परित्याग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पहल के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। शो सोमवार से शुरू हो गया है। सामाजिक बदलाव लाने और बालिकाओं के प्रति लैंगिक पक्षपात को दूर करने के उद्देश्य से, इस सहयोग के माध्यम से कलर्स का उद्देश्य बालिका परित्याग की सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता फैलाना है।'डोरी' का उद्देश्य लोकप्रिय संवाद पैदा करना और इस तरह से बालिका परित्याग के मुद्दे पर जागरूकता फैलाना है। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा,जिस तरह किसी देश की प्रगति इस बात से निश्चित होती है कि वहां महिलाओं और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसी तरह मनोरंजन का प्रभाव इस बात से निर्धारित होता है कि वह मानसिकता को कैसे बदल सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पहल के माध्यम से लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में काफी प्रगति की है। कलर्स बालिका परित्याग की महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या पर एक शो डोरी बनाने के लिए, इस पहल में शामिल हो गया है।



मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों ने लूटी महफिल





बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन किया। इसमें नीता अंबानी, रेखा, सलमान खान, गौरी खान, माधुरी दीक्षित, करण जौहर, रवीना टंडन और कई अन्य हस्तियां शामिल हुई। वीडियो में मनीष को फोटोग्राफरों का अभिवादन करते हुए और हैप्पी दिवाली विश करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, दिवाली का सीजन अब शुरू हो रहा है। वह ब्लैक आउटफिट में नजर आए। इस दिवाली पार्टी में नीता अंबानी अपनी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंची। पार्टी में सलमान अपने सिग्नेचर स्वैग और स्टाइल में नजर आए। एक्टर ने फुल स्लीव्स ब्लू टी-शर्ट, ब्लैक कार्गो पैंट और मैचिंग बूट्स पहने थे। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा गोल्डन साड़ी और फुल स्लीव्स ब्लाउज में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने नेकपीस, मैचिंग मांगटीका, चूड़ियां और झुमके के साथ अपने लुक को पूरा किया। गौरी खान ने पार्टी के लिए एथनिक लुक चुना। पार्टी में माधुरी दीक्षित के साथ उनके पति डॉक्टर नेने भी नजर आए। ऐश्वर्या राय बच्चन ने पार्टी के लिए रेड कलर का कुर्ता- शरारा सेट के साथ मैचिंग दुपट्टे को चुना। उन्होंने हाथ में ग्लोडन क्लच के साथ अपने लुक को पूरा किया। पार्टी में शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, वरुण धवन और नताशा दलाल, पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा, फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर जैसे बॉलीवुड के लवबर्ड्स की भी मौजूदगी देखी गई।

'टाइगर-3' के लिए लिया कड़ा प्रशिक्षण : कैटरीना कैफ

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ 'टाइगर-3' फिल्म की शूटिंग के लिए कड़े प्रशिक्षण से गुजरी हैं और उनका कहना है कि यह उनकी सीमा से परे जाने, अपनी सहनशक्ति को परखने और 'खुद के भीतर की ताकत को जानने' वाला अनुभव था। कैटरीना इस फिल्म में भी आईएसआई की पूर्व एजेंट जोया का किरदार निभा रही हैं जबकि उनके साथ सुपरस्टार सलमान खान रॉ एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को मनीष शर्मा ने निर्देशित किया है। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए जब टाइगर का नाम आता है तो यह अपनी सीमा से परे जाने, सहनशक्ति का परीक्षण करने और खुद के भीतर की ताकत को तलाशने का अनुभव है।' कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के लिए प्रशिक्षण के कई वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया,'किसी ने मुझसे कहा, 'दर्द भी एक अन्य तरह का एहसास है... इससे मत डरो, पीड़ा से मत भागो। कई दिनों तक मुझे थकान रही और मैंने महसूस किया कि यह समय अलग है। मेरा शरीर जख्मी हो गया था लेकिन मैं खुद से कहती थी कि इसे चुनौती की तरह लो और देखो कि आज तुम कितना सामना कर सकती हो।' 'टाइगर-3' दिवाली को यानी 12 नवम्बर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है।

अभिनेत्री रश्मिका काट-छांट करके बनाए गए वीडियो से आहत

दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने खुद के काट-छांट करके बनाए गए वीडियो (डीपफेक वीडियो) के वायरल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को कहा कि यह 'बहुत डरावना' है कि तकनीकी का दुरुपयोग किया जा रहा है, फिल्म 'गुडबाय' में मंदाना के सह कलाकार अमिताभ बच्चन ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

'डीपफेक' एक डिजिटल विधि है जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता किसी व्यक्ति की छवि को किसी दूसरे व्यक्ति की छवि से आसानी से बदल सकता है। तथ्य की जांच करने वाले एक व्यक्ति ने ब्रिटिश-भारतीय सोशल मीडिया हस्ती जारा पटेल के मूल वीडियो के साथ 'डीपफेक वीडियो' क्लिप को पोस्ट किया और उन्होंने भारत में 'डीपफेक' से निपटने के लिए एक कानूनी और नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता की मांग की। बच्चन इस पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। बच्चन ने कहा, 'हां यह कानून (कार्रवाई के लिहाज से) मजबूत मामला है।' मंदाना ने इंस्टाग्राम के माध्यम से भी अपनी चिंता व्यक्त की। मंदाना ने कहा कि वह वीडियो देखकर 'वास्तव में आहत' हुईं, जिसमें एक लिफ्ट के अंदर कसरत करने के दौरान पहनी जाने वाली काले रंग की परिधान (वनसी) में एक महिला को दिखाया गया है।



■ अमिताभ ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

छठ गीत 'पुरइन के पात पर उगेलेन सुरज देव' रिलीज

गायिका प्रियंका सिंह, अभिनेत्री माही श्रीवास्तव का छठ गीत'पुरइन के पात पर उगेलेन सुरज देव'रिलीज हो गया है। छठ गीत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इस गीत को प्रियंका सिंह ने गाया है और इस गीत को उनकी माँ निर्मला सिंह ने लिखा है।



इसके वीडियो में ट्रेडिशनल लुक में पियरी पहिने नाक से लेकर पूरी मांग तक सिंदूर लगाये माही श्रीवास्तव एकदम छठ माता की भक्तिन लग रही है। गाने के वीडियो में माही श्रीवास्तव सूरज की तरफ ताकते हुए अपनी सहेलियों व छठ बरतियों से कह रही है कि'पुरइन के पात पर उगेलेन सुरज देव झाँके झुमके, ए करेलु छठ बरतिया से झाँके झुमके..छठ गीत के निर्माता रत्नाकर कुमार है। निर्मला सिंह के लिखे इस गीत को संगीत से विनीत शाह ने सजाया है।

जयपुर एयरपोर्ट के नए स्टेट टर्मिनल भवन का भूमि पूजन, पहले चरण में खर्च होंगे 19.62 करोड़

राजस्थान में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का हो रहा निर्माण : भजनलाल



जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बेहतर समन्वय ने परिवहन के क्षेत्र में विकास कार्यों को नई दिशा दी है। प्रदेश में हवाई, रेल एवं सड़कों के तेज विकास से आमजन को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर नवीन स्टेट टर्मिनल भवन के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के मद्देनजर डबल इंजन की सरकार राजस्थान में परिवहन सुविधाओं को आधुनिक और आवागमन को अधिक सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में नवीन स्टेट टर्मिनल भवन का भूमि पूजन हवाई सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवीन स्टेट टर्मिनल भवन परियोजना के लिए 52 करोड़ 35 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना के पहले चरण में 19 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से स्टेट टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन में कार्यालय के साथ दो वीआईपी लाउंज, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, 10 विश्राम कक्ष, ट्रेनिंग कक्ष, कैफे और सुरक्षा जांच क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, इस भवन में आधुनिकता के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखेगी। परियोजना के दूसरे चरण में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए हैंगर तथा टारमेक का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजना के लिए ए.ए.आई. ने राज्य सरकार को 12 हजार 778 वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोटा, किशनगढ, बाड़मेर एवं बीकानेर में हवाई संपर्क विस्तार पर कार्य किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री ने इसी वर्ष जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। इस नवीन भवन से हवाई अड्डे की क्षमता प्रतिवर्ष 12 लाख यात्रियों से बढ़कर 20 लाख यात्रियों तक पहुंच गई है। वहीं, जयपुर और कोटा के टर्मिनल भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार किशनगढ़ हवाई अड्डे और भीलवाड़ा में हमीरगढ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू हो चुके हैं। झालावाड़, सीकर, झुंझुनूं एवं श्रीगंगानगर में एफटीओ की स्थापना के लिए भूमि आवंटन और उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि उपलब्ध करवायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार और रेलवे सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष 10 हजार 228 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है। 76 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक के रेलवे कार्य प्रगति पर हैं और अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। वहीं, नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से हमारा प्रदेश सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। प्रदेश में 1 हजार 192 किलोमीटर लम्बाई के एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ है, यह देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। आज देश के एक चौथाई नेशनल एक्सप्रेस-वे राजस्थान से होकर गुजरते हैं।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण कर रही है। कनेक्टिविटी के विकास और विस्तार का प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रदेश के किसान अपनी उपज मंडियों तक आसानी से पहुंचाएं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलें। साथ ही, उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिले और पर्यटकों के लिए राज्य में सफर अधिक सुगम बने। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिला का पूजन कर नींव में स्थापित की तथा हवन में पूर्णाहुति दी।

उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में नवीन स्टेट टर्मिनल भवन के प्रतीकात्मक मॉडल, संपूर्ण साइट प्लान, ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, विधायक डॉ. कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, बालमुकुन्दाचार्य, महापौर सुनील कोठारी, उपमहापौर सरोज कंवर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव नागरिक उड्डयन नवीन जैन सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आस्था के धाम तनोट माता मंदिर का होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री ने की तनोट माता मंदिर पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा



जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर तनोट माता मंदिर की पुनर्विकास परियोजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने मंदिर के समग्र विकास की योजना बनाई है।

इसके अंतर्गत यात्रियों के ठहराव, पार्किंग सहित विभिन्न बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि राज्य सरकार तनोट माता मंदिर की पुनर्विकास परियोजना के लिए भूमि आवंटित कर चुकी है। वहीं, परियोजना रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, पर्यटन शासन सचिव शुचि त्यागी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण, निगम ने शुरू किया पानी का छिड़काव



जयपुर (कासं)। दीपोत्सव के बाद राजधानी में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के साथ अब नगर निगम ने हवा की क्वालिटी सुधारने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। शहर में बढ़े वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निगम की ओर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए एंटी स्मॉग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इन मशीनों को अलग-अलग इलाकों में घूमाकर हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी और अन्य कारणों से शहर की एयर क्वालिटी प्रभावित हुई है। ऐसे में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एंटी स्मॉग मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों से पानी की बेहद हल्की फुहार छोड़ी जाती है।

इससे हवा में मौजूद धूल और कुछ प्रदूषक कण पानी की बूंदों के साथ नीचे बैठने में मदद मिलती है। निगम की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में इन मशीनों का संचालन कर रही हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर धूल और हवा में मौजूद कणों को कम किया जा सके। फिलहाल जयपुर में चार मशीनें अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं। इनमें एक मशीन मानसरोवर और मालवीय नगर क्षेत्र में, दूसरी विद्याधर नगर और झोटवाड़ा क्षेत्र में, तीसरी सिविल लाइंस और किशनपोल क्षेत्र में और चौथी हवामहल और आमेर जोन में लगाई गई है। ताकि शहर के अलग-अलग हिस्सों में मशीनों के जरिए हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिले। बता दें कि पहली बार दीपोत्सव के बाद नगर निगम का यह अभियान शहर की सफाई के साथ वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई : 41.510 किलोग्राम गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार

ऑपरेशन में बलारा थाना क्षेत्र में स्विफ्ट कार से बरामद हुआ गांजा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपये आंकी गई



जयपुर (कासं)। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर जिले के बलारा थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट कार से 41 किलो 510 ग्राम अवैध गांजा जब्त कर तस्कर राकेश कुमार निवासी खिरोड़, जिला झुंझुनूं को गिरफ्तार करवाया है। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपये आंकी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) बिपिन कुमार पाण्डेय के निर्देशन में सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा सक्रिय हार्डकोर बदमाशों, इनामी अपराधियों तथा अवैध मादक पदार्थ एवं हथियार तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार 11 नवंबर को देर रात यह कार्रवाई की गई।

महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (अपराध) के.बी. वंदना के मार्गदर्शन, उपमहानिरीक्षक पुलिस दीपक भार्गव के सुपरविजन तथा उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह और कुलदीप सिंह की टीम को आसूचना संकलन के लिए सीकर और फतेहपुर क्षेत्र में भेजा गया था। इसी दौरान टीम के हेड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि स्विफ्ट कार नंबर ऋ18 ष्टस्न 2905 में संदिग्ध सामान लेकर सीकर से लक्ष्मणगढ़ होते हुए झुंझुनूं की ओर जाया जा रहा है। सूचना पर एसपी सीकर संजीव नैन से समन्वय किया गया। जिनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल और सीओ लक्ष्मणगढ़ जाकिर अख्तर के पर्यवेक्षण में सीआईडी सीबी की टीम ने थानाधिकारी बलारा एवं पुलिस जाप्ते के साथ संयुक्त कार्रवाई की। लक्ष्मणगढ़ की ओर से आ रही संदिग्ध स्विफ्ट कार को पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया तो चालक ने कार को लहराते हुए भगाने की कोशिश की। पुलिस टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार को रुकवाया। चालक ने कार लॉक कर दी और दरवाजे नहीं खोले। वह दोबारा कार भगाने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया।

सीओ लक्ष्मणगढ़ अख्तर की मौजूदगी में बलारा थानाधिकारी एवं पुलिस जाप्ते ने कार की तलाशी ली। कार की पिछली सीट के पास रखे पीले कट्टे से 16 किलो 370 ग्राम तथा डिग्गी में रखे सफेद कट्टे से 25 किलो 140 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों कट्टों में गांजे के कुल 20 पैकेट रखे हुए थे। इस प्रकार कुल 41 किलो 510 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इस संबंध में पुलिस थाना बलारा, जिला सीकर में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मामले का अनुसंधान पुलिस थाना दादिया के थानाधिकारी संजय पूनिया द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार ने बताया कि गांजा और कार उसके साथी विकास कुमार धींवा निवासी सेवापुरा, खिरोड़ की है। आरोपी के अनुसार विकास कुमार कुछ दूरी पहले कार से उतर गया था और उसने आगे पहुंचकर फोन

मोडिफाइड साइलेंसर से दहशत फैलाने वालों पर राजस्थान पुलिस की सख्ती

235 दुपहिया वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई, 235 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर रोड रोलर से किए नष्ट



जयपुर (कासं)। महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार आमजन को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराने तथा सड़क सुरक्षा और जनसुविधा को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज के निर्देशन में यातायात पुलिस कोटा शहर ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज धमाकों जैसी आवाज से आमजन में दहशत फैलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अभियान के दौरान 235 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 235 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए। जब्त साइलेंसरों को वाहनों से निकलवाकर रोड रोलर से नष्ट किया गया। एसपी ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर से अचानक तेज धमाकों जैसी आवाज निकलने से राहगीरों और आमजन को परेशानी होती है। इससे वाहन चालकों का ध्यान भटकने और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे साइलेंसर लगवाना नियम विरुद्ध है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय है।

साइलेंसर लगाने वाले मिस्त्रियों और विक्रेताओं पर भी होगी कार्रवाई

एसपी गौतम ने बताया कि कोटा पुलिस अब मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के साथ ही इन्हें लगाने वाले मिस्त्रियों तथा बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। इसके लिए वाहन चालकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित लोगों को चिह्नित किया जाएगा।

कोटा पुलिस की आमजन से अपील

कोटा पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने तथा दुपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग नहीं करने की अपील की है। जिन वाहन चालकों ने ऐसे साइलेंसर लगवा रखे हैं, वे उन्हें तत्काल हटवा लें। आमजन मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मिस्त्रियों, विक्रेताओं एवं ऐसे साइलेंसर लगे वाहनों की फोटो या वीडियो पुलिस नियंत्रण कक्ष कोटा शहर के व्हाट्सऐप नंबर 9530442777 पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर 07442350741 पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। एसपी ने बताया द्यद्ध राजस्थान पुलिस आमजन की सुविधा, सड़क सुरक्षा और शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों के

'दीवाली खुशियों वाली' प्रतियोगिताओं की तारीख बढ़ी, अब 19 तक आवेदन

जयपुर। जयपुर नगर निगम द्वारा दीपावली के अवसर पर आयोजित 'दीवाली खुशियों वाली' प्रतियोगिताओं को लेकर शहरवासियों, व्यापारियों, संस्थागत प्रतिष्ठानों एवं वार्ड पार्षदों में मिल रहे उत्साहजनक प्रतिसाद को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पार्षदों एवं आवेदकों की मांग पर अब प्रतियोगिताओं में प्रविष्टियां 19 नवंबर 2026, गुरुवार तक स्वीकार की जाएंगी।

प्रतिभागियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब सभी सातों श्रेणियों में दीपावली के दौरान की गई सजावट की मोबाइल गैलरी में पहले से सुरक्षित तस्वीरें भी अपलोड की जा सकेंगी। यानी जिन नागरिकों, व्यापारियों एवं संस्थानों ने दीपावली के अवसर पर अपने घर, प्रतिष्ठान, कार्यालय या बाजार को सजाया था और उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में सुरक्षित रखी हैं, वे भी अब उन तस्वीरों के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। इसके लिए दोबारा सजावट करने या नई तस्वीरें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

न्यूज इनबॉक्स

पंचायतीराज चुनाव : प्रशिक्षण के बाद आज रवाना होंगे मतदान दल

जयपुर (कासं)। पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जयपुर जिले में चतुर्थ चरण के मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चतुर्थ चरण के लिए शुक्रवार, 13 नवंबर को मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण प्रातः 9.00 बजे से रहेगा। इस दौरान मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम के संचालन, बैलेट पेपर तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के पश्चात मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि चतुर्थ चरण के तहत जयपुर जिले की चार पंचायत समितियों बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इस चरण में कुल 140 ग्राम पंचायतों के 446 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें पंचायत समिति बस्सी की 42 ग्राम पंचायतों के लिए 145 मतदान केंद्र, तूंगा की 24 ग्राम पंचायतों के लिए 74 मतदान केंद्र, जमवारामगढ़ की 42 ग्राम पंचायतों के लिए 129 मतदान केंद्र तथा आंधी की 32 ग्राम पंचायतों के लिए 98 मतदान केंद्र निर्धारित हैं। उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए शनिवार, 14 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पंच एवं सरपंच पदों के लिए रविवार, 15 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद सोमवार, 16 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। उपसरपंच पद के लिए मंगलवार, 17 नवंबर को चुनाव आयोजित किया जाएगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सभी चरणों की मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान दलों की रवानगी, निर्वाचन सामग्री वितरण, परिवहन एवं प्रशिक्षण सहित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी निर्वाचन कार्मिकों को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।

एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित, जिले में 45 लाख 33 हजार 470 मतदाता

जयपुर (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जयपुर जिले की एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जयपुर जिले में कुल 45 लाख 33 हजार 470 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 23 लाख 50 हजार 709 पुरुष, 21 लाख 82 हजार 680 महिला एवं 81 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्हें विधानसभा स्तर पर प्रारूप मतदाता सूची की एक-एक प्रति हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने के संबंध में अवगत कराया गया। प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट http://election. rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्रवार प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार शाहपुरा में 2 लाख 39 हजार 448, चौमूं में 2 लाख 58 हजार 323, फुलेरा में 2 लाख 66 हजार 605, दूदू में 2 लाख 55 हजार 187, झोटवाड़ा में 4 लाख 21 हजार 209, आमेर में 2 लाख 95 हजार 856, जमवारामगढ़ में 2 लाख 31 हजार 651, हवामहल में 2 लाख 46 हजार 317, विद्याधर नगर में 3 लाख 25 हजार 379, सिविल लाइंस में 2 लाख 8 हजार 912, किशनपोल में 1 लाख 77 हजार 319, आदर्श नगर में 2 लाख 41 हजार 188, मालवीय नगर में 1 लाख 98 हजार 321, सांगानेर में 3 लाख 34 हजार 389, बगरू में 3 लाख 52 हजार 999, बस्सी में 2 लाख 42 हजार 655 तथा चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 37 हजार 712 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवाने, किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करवाने अथवा वर्तमान प्रविष्टियों में संशोधन करवाने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके लिए नियमानुसार प्रपत्र 6, 7 एवं 8 में से जो भी प्रपत्र उपयुक्त हो, उसमें आवेदन किया जा सकता है। आवेदक ये आवेदन ऑनलाइन माध्यम से वोटर सर्विस पोर्टल अथवा ECINET ऐप के जरिए, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में अथवा बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की सूची प्रत्येक सप्ताह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। साथ ही उक्त सूचियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं संबंधित मतदान केंद्रों पर भी चस्पा करवाई जाएंगी। निर्धारित अवधि के दौरान प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में निर्णय के 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, भीलवाड़ा

पता:- महाराणा टाकीज के पास, भीलवाड़ा राजर (311001) टेलीफोन 01482-236355 ई-मेल dao.bhl.ayu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-AHWC/ ट्रेनिंग निविदा/2026-27/2036 दिनांक:-05.11.2026

खुली बोली आमन्त्रण निविदा संख्या 05/2026-27

(दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के व्यवस्थार्थ खुली निविदा)

इस कार्यालय के नियन्त्राणाधीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत कार्मिकों का दो दिवसीय आवासीय में ट्रेनिंग चाय नाश्ता, भोजन व्यवस्थार्थ कार्य करवाये जाने हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति में उक्त कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मों / एजेन्सी/व्यक्ति से निम्नानुसार दिनांक 12.11.2026 तक मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

NIB CODE-AYU2627A0312

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित लागत	UBN CODE
1	आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत आशा/ए.एन.एम. और आयुर्वेद कम्पाउण्डर/नर्स का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम करवाने बाबत	06.00 लाख	AYU2627 SSOB00318

बिड शर्तें, दस्तावेज एवं अन्य विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे और डाउनलोड किये जा सकते है।

उपनिदेशक
आयुर्वेद विभाग, भीलवाड़ा

DIPR/C/18341/2026

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक कैलाश त्रिवेदी के लिए उदय प्रिन्टर्स 43-ए, माली कॉलोनी चांदपोल बाहर जयपुर से मुद्रित एवं डी-38, प्रधानपथ, चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक कैलाश त्रिवेदी* । *पीआईबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार।
फोनः 0141-4038281, **Email:-** lokjeewanjpr@gmail.com **भीलवाड़ा कार्यालयः** 207-214, नागौरी गार्डन, लोकजीवन कॉम्पलेक्स, भीलवाड़ा। **फोनः** 01482-355985, Email:- lokjeewan@gmail.com, **मो.** 8306792625